फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 75 संख्याः 48 प्रभात जयपुर, बुधवार 18 सितम्बर, 2024 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Rashtradoot

Metro

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

He Trusted and was delivered Trust

An airman came running to the cockpit to tell him that an important letter had to go, and his signatures were required. Shyam, in all sincerity, signed at the bottom of the paper without even going through it.

Party @ Paro

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उनसे प्रेरणा लेने का आव्हान किया

बिड़ला सभागार में विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह

जयपुर, 17 सितंबर (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज 10 हजार करोड़

- मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में दस हजार करोड़ रु. से अधिक के कार्यों का शिलान्यास किया और इसे विकसित राजस्थान की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 86 नगर पालिकाओं को 50 करोड़ रु. की आर्थिक सहायता करने की भी घोषणा की।

रूपए से अधिक के कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण विकसित राजस्थान के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर उन्होंने 86 नगर पालिकाओं को 50 करोड़ रूपये की आर्थिक सहायता जारी करने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर बिड़ला सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कई लोककल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की।

मुख्यमंत्री मंगलवार को बिड़ला सभागार में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव, पी.एम. आवास योजना-ग्रामीण, स्वच्छता ही सेवा अभियान, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मा) वाउचर योजना और अन्य विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ''सेवा पखवाड़ा'' मनाएगी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर दो अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसमें रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और मोदी के जीवन पर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उन्होंने कहा, रक्तदान, वृक्षारोपण, दिल्ली में झुग्गी बस्तियों का सफाई अभियान जैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे। देश मोदी के नेतृत्व में विकसित

- भाजपा अध्यक्ष जे.पी.नड्डा ने बताया कि सेवा पखवाड़ा मोदी के जन्मदिन से शुरु होकर महात्मा गांधी के जन्मदिन तक चलेगा।

भारत की ओर बढ़ रहा है।

नड्डा ने कहा मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में कई क्रांतिकारी काम किए गए हैं। इसमें इन्फ्रास्टक्चर के लिए तीन लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं तथा 25,000 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है और 62,500 किलोमीटर लम्बी ऑल वैदर सड़कें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबो के लिए 3 करोड़ घरों को मंजूरी दी है और यूनीफाइड पेंशन योजना को स्वीकृति देने के साथ 15 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी शुरू किया गया है।

चुनाव के पूर्व केजरीवाल कई मनलुभावन स्कीम लागू करना चाहते थे

पर जमानत की शर्तों के कारण उनके हाथ बंध गये थे, अतः आतिशी को लाना पड़ा नये मुख्यमंत्री के रूप में

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर छः महीने दिल्ली के तिहाड़ जेल में बिताने के बाद जमानत पर बाहर आए अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आतिशी मारलेना को अपना उत्तराधिकारी चुना है।

अगले वर्ष के आरंभ में दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं, केजरीवाल चुनाव से पूर्व दिल्ली की जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं तथा अन्य स्कीम शुरु करना चाहते थे, लेकिन जमानत की शर्त के रुप में सुप्रीम कोर्ट ने उनके हाथ बांध दिए, यह कहकर कि वो किसी फाइल वगैरह पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, ऐसे में केजरीवाल ने कथित रुप से निर्णय लिया कि वो पद छोड़ देंगे और दिल्ली चुनाव के लिए संघर्ष करेंगे।

उन्हें उम्मीद है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के रुप में वापस आ सकते हैं और मुख्यमंत्री के रुप में अपने कार्य कर पाएंगे।

उनके अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया है। सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल

- आतिशी के मां-बाप, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, ने अपनी पुत्री का नाम मारलेना (मार्कसिस्ट-लेनिनिस्ट) रखा।
- केजरीवाल को पूरा भरोसा था, कि इस कट्टर वामपंथी पृष्ठभूमि के बाद आतिशी और कुछ भी करें, भाजपा से हाथ नहीं मिलायेंगी।
- इस विश्वास के कारण ही केजरीवाल ने आप पार्टी के मुख्यमंत्री पद के अन्य उम्मीदवारों के बजाय आतिशी को चुना, मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी सौंपने के लिए।
- एक उल्लेखनीय बात यह भी है, कि भाजपा की चुनावी गणित का आधार यह ''कैल्कुलेशन'' था, कि दिल्ली में शीघ्र ही राष्ट्रपति शासन लागू होगा, प्रशासनिक पेचीदगियों के कारण और भाजपा की राह आसान हो जायेगी। पर, केजरीवाल ने 'इस्तीफा' देकर व नया मुख्यमंत्री बनवाकर, भाजपा की ''प्लानिंग'' पर पानी फेर दिया।

कई तरह के विकल्पों पर विचार कर रहे थे, जिसमें उनकी पत्नी सुनीता तथा दिल्ली विधानसभा स्पीकर का भी नाम था, लेकिन अंततः उन्होंने आतिशी का नाम फाइनल किया, क्योंकि, दिल्ली में आतिशी एक जाना-माना चेहरा हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उन्होंने पूरा मोर्चा संभाल रखा था।

आतिशी ना केवल एक जुझारु योद्धा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ममता बनर्जी ने अपने पसंदीदा पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर किया

मुख्यमंत्री ने राज्य की मेडिकल व्यवस्था पर सालों से कुण्डली मार कर बैठी अफसर शाही के कुछ अफसरों का तबादला किया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। ममता बनर्जी जो ''एग्री यंग वुमन'' के नाम से विख्यात रही हैं, ने अपने लम्बे राजनैतिक जीवन में पहली बार हार मानी है। उन्हें जूनियर डॉक्टर्स की मांग मानकर अपने प्रिय पुलिस अफसर विनीत गोयल को कलकत्ता पुलिस प्रमुख के पद से हटाना पड़ा।

नए कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा की प्रतिष्ठा दबंग व कठोर पुलिस अफसर की है, उन्होंने जंगल महल में माओवादी बगावत को दबाने में भारी सफलता प्राप्त की थी।

जूनियर डॉक्टर्स के आंदोलन से पता लगा कि राज्य के समूचे मैडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर कुछ तृणमूल नेताओं

- पर आन्दोलनकारी जूनियर डॉक्टर इन तबादलों/बर्खास्तगी को पर्याप्त नहीं मान रहे, तथा आंदोलन वापस लेने को राजी नहीं हुए हैं अभी तक।
- सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सुनवाई के बाद, ममता बनर्जी के प्रति रुख कड़ा किया, तथा युवा डॉक्टर के ''रेप'' व ''हत्या'' के बाद, पुलिस की तहकीकात व अन्य कार्यवाही को बहुत लचर माना।
- अतः जूनियर डॉक्टरों ने आन्दोलन को वापस लेने व काम शुरू करने के बारे में कोई खास रूचि नहीं दिखाई है।

की कितनी गहरी पकड़ है। लेकिन वरिष्ठ तृणमूल नेता सुगत रॉय ने उन परिवर्तनों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कुछ आई.पी.एस. अफसरों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगा देने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये युवाओं के लिए लॉलीपॉप है। उन्होंने कहा कि यह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

खड़गे ने मोदी को जन्मदिन की बधाई दी

-जाल खंबात-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और महाराष्ट्र के एक विधायक द्वारा राहुल गांधी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रधानमंत्री

- बधाई के साथ ही मोदी से महाराष्ट्र के उस विधायक की शिकायत भी की जिसने राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को दस लाख रु. देने की बात कही थी।

का ध्यान खींचा। उक्त विधायक ने कहा था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की जीभ काटने वाले को वे दस लाख रुपये देंगे।

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में खड़गे ने कहा कि सत्तारुढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच सम्मानजनक मतभेदों का लम्बा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीतीश कुमार के लैंड सर्वे से बिहार में सत्तारुढ़ गठबंधन में खटास उभरी

नीतीश ने आनन फानन में एक प्राइवेट एजेंसी से जुलाई में लैंड सर्वे शुरु करवा दिया था

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई ''लैण्ड सर्वे'' की पहल के कारण, राज्य विधानसभा चुनावों के एक वर्ष पहले ही राजनैतिक घबराहट पैदा हो गई है। इस पहल को लेकर, सत्तारूढ़ गठबन्धन के पार्टनरों के बीच की असहमतियाँ खुले में आ गई हैं।

एकाएक लिये गये इस निर्णय के तहत तथा बिना किसी पूर्व-तैयारी के, कुमार ने जुलाई मे एक प्राइवेट एजेंसी को यह काम सौंप दिया कि वह कृषि भूमि पर जी.पी.एस. डेटा लॉन्च करे। और सर्वे का काम शुरू हो गया। नीतीश ने जमीन के मालिकों तथा किसानों से कहा कि यह सर्वे ऐसे रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कराया जा रहा, ताकि यह स्थापित हो सके कि वे लोग सम्बन्धित जमीन के

- लैंड सर्वे में जमीनों के मालिकों से जमीन के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिससे राज्य में भारी पैमाने पर रिश्वत का खेल शुरु हो गया है।
- गरीब किसानों को जमीनों के कागज जुटाने के लिए अधिकारियों व वकीलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जनता में नाराज़गी उभर रही है, जो आगामी चुनाव में सत्तारुढ़ गठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है।

वास्तविक मालिक हैं।

पटना स्थित ''ए.एन.सिन्हा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज़'' के पूर्व निदेशक प्रो. डी.एम. दिवाकर ने कहा है, ''यह कथन दायें हाथ को गर्दन के पीछे होकर नाक पकड़ने के समान है। राज्य सरकार के पास ''लैंड रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट के शिड्यूल-1 तथा शिड्यूल-2 में जमीन के रिकॉर्ड्स पहले से ही मौजूद हैं। सरकार को चाहिए था कि वह राजस्व-रिकॉर्ड्स को सरल करके, सरकारी वेबसाइट पर डिसप्ले कर देती तथा किसानों से उनकी प्रतिक्रियाएं मांग लेती। चूँकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए घोर उलझन की स्थिति पैदा हो गई है।''

पूरे राज्य में, भ्रम उलझन तथा डर फैल गया है तथा एक नया रिश्वत-उद्योग अस्तित्व में आ गया है क्योंकि किसान जमीन के रिकॉर्ड हासिल करने के लिए दलालों, वकीलों तथा अधीनस्थ नौकरशाही के अधिकारियो के पास चक्कर काट रहे हैं। जहाँ मुख्यमंत्री कुमार ने यह घोषणा कर दी है कि सर्वे का काम अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावो से पहले पूरा हो जाएगा, वहीं, भाजपा ने घोषणा की है कि सर्वे की पूर्णता के लिए कोई अन्तिम तिथि नहीं होगी।'' भाजपा नेता तथा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को घोषणा की कि सरकार ''सर्वे-प्रक्रिया को तब तक जारी रखेगी, जब तक लोग अपने दस्तावेजों की व्यवस्था नहीं कर लेते।'' एच.ए.एम., जो एन.डी.ए. का घटक दल है, के अध्यक्ष जीतन राम माँझी ने हाल ही में ''भूमि सम्बन्धी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें बढ़ने'' की बात कही थी। आर.जे.डी. के तेजस्वी यादव तथा नव-

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जेडीए की जमीन पर अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जयपुर, 17 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने गोपालपुरा बाईपास पर गुर्जर की थड़ी के पास जेडीए की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में प्रमुख यूडीएच सचिव, जेडीए सचिव, जेडीसी, जेडीए

- राजस्थान हाईकोर्ट ने गुर्जर की थड़ी के पास जे.डी.ए. की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में यू.डी.एच. सचिव, जे.डी.ए सचिव तथा जे.डी.सी. व अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए।

के विधि निदेशक और मुख्य प्रवर्तन अधिकारी सहित अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश संजय शर्मा की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनीं आतिशी

आतिशी, केजरीवाल की सर्वाधिक विश्वस्त व आप सरकार की सबसे अनुभवी मंत्री हैं

-डॉ. सतीश मिश्रा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 17 सितम्बर। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर-दम्पत्ति विजय कुमार सिंह तथा तृप्ता वाही की पुत्री आतिशी की विद्यालयी शिक्षा दिल्ली के स्प्रिंगडेल्स स्कूल में हुई। प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन्स से उन्होंने ग्रेजुएशन तथा पोस्ट-ग्रेजुएशन (इतिहास) किया। तियालिस वर्षीय रोड्स स्कॉलर तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की छात्रा रहीं आतिशी के पास इस समय दिल्ली सरकार के सर्वाधिक मन्त्रालय हैं, जिनमें वित्त, शिक्षा, बिजली, सार्वजनिक निर्माण विभाग एव सेवाएं शामिल हैं।

वे आप की संस्थापक सदस्य थीं तथा उन्होंने आप की नीतियों को आकार देने में मुख्य भूमिका निभाई थी। वे 2013 की ''मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी'' की प्रमुख सदस्य थीं।

आतिशी ने मध्यप्रदेश के एक गाँव में 7 साल रहकर, ऑर्गेनिक कृषि तथा प्रगतिशील शिक्षा पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित रखा। पार्टी के एक पदाधिकारी ने कहा कि उनके इस अनुभव ने राजनैतिक परिवर्तन के प्रति उनकी निष्ठा को मजबूत करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई।

वे सरकारी स्कूलों के कायाकल्प का सशक्त माध्यम एवं अत्यधिक मददगार रही हैं। शैक्षिक सुधारों के क्रियान्वयन में उनकी भूमिका के फलस्वरूप, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। उनका प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र से और आगे जाकर, दिल्ली के जल-संकट तथा महिला-सुरक्षा जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों तक भी पहुँचा है।

कालकाजी सीट से विधायक चुनी गईं आतिशी दिल्ली केबिनेट में मार्च, 2023 में उस समय शामिल हुईं, जब सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति, जो अब रद्द कर दी गई है, को लेकर इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद से ही,

- आप की राजनीति में आतिशी के उदय का संकेत तब मिला जब 2023 स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में केजरीवाल के जेल में होने पर आतिशी को झंडा फहराने के लिए चुना गया, हालांकि केन्द्र सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया था।
- आप की स्थापना से लेकर सरकार बनाने सहित हरेक मुहिम में आतिशी ने केजरीवाल का पूरा साथ दिया।
- आतिशी की मां तृप्ता वाही और पिता विजय कुमार सिंह दिल्ली युनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। खुद आतिशी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि बेहद शानदार रही है।

उन्होंने सरकारी प्रोजेक्टों में अग्रणी भूमिका निभाई है। केजरीवाल और सिसोदिया के जेल चले जाने के बाद, उन्होंने प्रायः आप के चेहरे के रूप में काम किया है।

आतिशी का नेतृत्व 2023 के स्वतन्त्रता दिवस समारोह के दौरान फोकस में आया, जब केजरीवाल की गैरमौजूदगी मे उनका चयन राष्ट्रध्वज फहराने के लिये किया गया। यद्यपि दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस योजना को रोक दिया था, लेकिन यह चयन पार्टी के अन्दर उनके उदय के एक प्रतीकात्मक क्षण का रूप ले चुका था।

2022 में उन्होंने न्यूयॉर्क में ''यूनाइटेड नेशन्स जनरल असैम्बली''(यू.एन.जी.ए.) को सम्बोधित करते हुए, दिल्ली को शहरी शासन-प्रशासन के लिए वैश्विक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया था।

जमीनी संगठनों में अपना केरियर शुरू करने के बाद, आतिशी पार्टी में निरन्तर उच्चतर सोपानों पर चढ़ती रही हैं। पिछले सप्ताह, पहले के केस में (बाद के केस में तो उन्हें जुलाई में ही राहत मिल गई थी।) केजरीवाल को जमानत देते समय, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि ''लम्बे समय तक उन्हें जेल में डाले रखना, उन्हें स्वतन्त्रता से अन्यापूर्ण तरीके से वंचित रखने के बराबर था।''

केजरीवाल ने रिहा होने के बाद कहा था, ''मुझे कानूनी अदालत से तो न्याय मिल गया, ... अब मुझे जनता की अदालत से न्याय मिलेगा। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल दोषी है या निर्दोष ? अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दीजिए।''

रविवार को केजरीवाल द्वारा की गई एकाएक घोषणा, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री पद से हट जाने की घोषणा की थी, को सुनकर, राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति में विस्मय की लहरें गुजर रही थीं। इस साहसिक कदम के जरिये, आप संयोजक ने अपने नैतिक कद को नई ऊँचाइयाँ प्रदान करने की कोशिश की थी, ताकि विपक्ष की ताकत थम कर रह जाए।

आबकारी नीति केस से सम्बन्धित आरोपों को लेकर, जब से केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में डाले गए थे, भारतीय जनता पार्टी चिल्ला-चिल्लाकर उनके इस्तीफे की माँग कर रही थी। केजरीवाल, जो सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग के लिए प्रसिद्ध हैं, अपने मतदाताओं के बीच बढ़ते जा रहे असन्तोष की और अधिक अवहेलना नहीं कर सकते थे। अपनी गिरफ्तारी के बाद भी, अपने पद पर बने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संशोधित परिणाम से बाहर हुए कांस्टेबलों को सेवा में रखा जाए

जयपुर, 17 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2020 के संशोधित परिणाम से बाहर हुई कांस्टेबलों को सेवा में बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के

- राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2020 परीक्षा के संशोधित परीक्षा परिणाम के कारण सेवा से बाहर किए गए कांस्टेबलों को बहाल करने के आदेश तो दिए पर इन्हें मैरिट में सबसे नीचे रखने का निर्देश भी दिये।

तहत इन्हें मेरिट सूची में सबसे निचले स्तर पर रखने को कहा है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश भीम सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)